स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) उत्तर प्रदेश

नगर की खबर
नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश

स्वच्छता टाइम्स

अंक 12 | दिनांक: 30 जून 2023

अच्छा कार्य करने वाली निकायों को मिलेगा 10 करोड़ का पुरस्कार : सीएम योगी

नवनिर्वाचित नगर निगमों के महापौर, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 17 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश के सभी नगर निकाय स्मार्ट सिटी के रूप में अपने आपको स्थापित कर सकते हैं। नगर विकास विभाग व गृह विभाग मिलकर अगले 06 माह में 17 नगर निगम व गौतमबुद्धनगर को सेफ सिटी के रूप में विकसित करने का कार्य करें। मुख्यमंत्री जी ने इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में नवनिर्वाचित नगर निगमों के महापौर, नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों के अध्यक्षों की एक दिवसीय कार्यशाला में अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित महापौर व अध्यक्षों को उनके सफल निर्वाचन की बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार व अन्य व्यावसायिक संस्थान मिलकर शहर में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का कार्य करें। इससे शहरों की सुरक्षा में वृद्धि होगी। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिगण नेतृत्व प्रदान करते हुए इन कार्यों को सम्पन्न करें। हमारे शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध किए जाएं। पिंक टॉयलेट, महिला हेल्प डेस्क सहित अन्य बेहतरीन व्यवस्थाएं महिलाओं के लिए सुनिश्चित की जाएं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, अच्छी सड़कें, सेफ सिटी के कार्य, आत्मनिर्भरता की दिशा में जैसे 05 से 07 पैरामीटर्स तय कर नगर निकायों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ जोड़कर उनके नम्बर तय करें। नम्बर 01 में आने वाले नगर निकाय अगले 02 वर्ष बाद ही नम्बर 01 की प्रतिस्पर्धा में शामिल होंगे। लेकिन नम्बर 01 में आने वाले नगर निकाय को अपनी तत्परता बनाए रखनी होगी, अन्यथा उसकी माइनस मार्किंग भी होगी। प्रदेश सरकार जनपद स्तर पर इन पैरामीटर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली नगर पंचायत को 01 करोड़ रुपये वर्ष में अतिरिक्त देगी। इसी प्रकार मण्डल स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर प्रथम स्थान पर आने वाली नगर पालिका परिषद को 02 करोड़ रुपये अतिरिक्त तथा राज्य स्तर पर इन पैरामीटर्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर प्रथम स्थान पर आने वाले नगर निगम को 10 करोड़ रुपये अतिरिक्त रूप में दिए जाएंगे।

जनपद स्तर पर पैरामीटर्स के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली नगर पंचायत को वर्ष में 01 करोड़ रु0, मण्डल स्तर पर प्रथम स्थान पर आने वाली नगर पालिका परिषद को 02 करोड़ रु0, राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पर आने वाले नगर निगम को 10 करोड़ रु0 अतिरिक्त दिए जाएंगे नगर विकास विभाग व गृह विभाग मिलकर अगले 06 माह में 17 नगर निगम व गौतमबुद्धनगर को सेफ सिटी के रूप में विकसित करें।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नवगठित नगर निकायों एवं नगर निकायों में शामिल किये गये नये क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए प्रदेश सरकार ने बजट की व्यवस्था की है। इन नये नगरीय क्षेत्रों में समग्र विकास की दृष्टि से विकास कार्य सम्पन्न किये जाएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर व विकसित बनाने के लिए टीमवर्क के माध्यम से कार्यों को क्रियान्वित करना होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नगर निकाय हैं। प्रदेश में कुल 762 नगरीय निकाय हैं, जिनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषदें व 545 नगर पंचायतें शामिल हैं। इन सभी 762 नगरीय निकायों में 02 चरणों में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से 35 दिन से कम समय में सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न हुए। इसके लिए उन्होंने प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस व नगर विकास विभाग को बधाई दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में नये भारत का निर्माण हो रहा है। हम सभी को इस नये भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता निभानी होगी। केन्द्र सरकार द्वारा विगत 09 वर्षों से नगरीय जीवन के कायाकल्प के लिए विभिन्न विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे शहरों में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन दिखायी दे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पी0एम0 स्वनिधि योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल योजना द्वारा शुद्ध पेयजल, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों/ योजनाओं द्वारा नगरीय क्षेत्र में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रदेश में वर्तमान में 54 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास प्रदान किए जा चुके हैं, जिनमें साढ़े 17 लाख आवास शहरी क्षेत्र के गरीब व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। वहीं पी0एम0 स्वनिधि योजना के अन्तर्गत लगभग 12 लाख स्ट्रीट वेण्डर्स को बैंक द्वारा ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। हर घर नल योजना द्वारा घरों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। हर घर नल योजना के संदर्भ में प्रत्येक नगर अपनी कार्ययोजना तैयार करे तथा यूजर चार्ज के साथ जल संसाधन के संरक्षण व प्रबन्धन के लिए मिलकर कार्य करें।

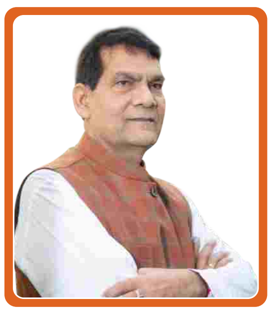

श्री ए0 के0 शर्मा
माननीय नगर विकास मंत्री
उत्तर प्रदेश

नगर किसी भी देश व प्रदेश का आईना और निवेश के चुम्बक होते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा प्रदेश काफी बड़ा है। प्रदेश की एक तिहाई जनता, लगभग 07 से 08 करोड़ नगरों में रहती है। सभी निकाय नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने तथा व्यवस्थापन पर विशेष ध्यान देते हुए नगरीय जीवन को और भी सुगम बनाएं। नगरीय निकायों में बरसात से पहले नाले व नालियों की सफाई, जल भराव वाले स्थानों का चिन्हीकरण, पेयजल आपूर्ति, दैनिक सफाई की व्यवस्था, संचारी रोगों के रोकथाम के लिए फागिंग, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन आदि कार्यों को सुनिश्चित कराएं। बरसात के दौरान शहरों में कहीं पर भी जल भराव की स्थित न बने, जिससे कि नागरिको को परेशानी हो। इसके लिए सभी नाले नालियों की तलछट सिल्ट सफाई, इन पर उगी झाड़ी-झाड़ियों एवं प्लास्टिक व पालीथीन की सफाई सुनिश्चित करें। सभी चोकिंग प्वाइन्ट को चिन्हित कर उचित प्रबंध किया जाए।

श्री राकेश राठौर 'गुरू'
माननीय नगर विकास मंत्री
माननीय नगर विकास राज्य मंत्री
उत्तर प्रदेश

मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और मा. नगर विकास मंत्री श्री एके शर्मा जी के कुशल निर्देशन में प्रदेश के नगरों में रहने वाली जनता का जीवन और भी सुगम हो गया है। नगरों की सफाई व्यवस्था और सुंदरता चर्चा का विषय बन चुकी है। जनता को स्वच्छ वातावरण के साथ ही विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कचरा मुक्त शहर की परिकल्पना को साकार करने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ सभी अधिकारिओं और जनता का भी सहयोग लगातार मिल रहा है, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। साथ ही शहर को स्वच्छ और सुन्दर बनाने में निरंतर सहयोग की प्रार्थना भी करते हैं।

कार्यक्रम की झलकियां

सभी निकाय प्रमुख महीने में एक दिन उठाएं झाड़ू : उप मुख्यमंत्री मौर्य

- **आत्मनिर्भर नगर निकाय बनाने का संकल्प लेकर जाएं नगर निकायों के अध्यक्ष : केशव प्रसाद मौर्य**

सभी अध्यक्ष और पार्षद महीने में एक बार अपने नगर क्षेत्र में साफ-सफाई स्वयं झाड़ू लगाकर करें। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नगर निकायों के अध्यक्ष अपने नगर निकाय को आत्मनिर्भर निकाय बनाने का संकल्प लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि जिस तरह की स्थानीय निकायों के अध्यक्षों की अभिमुखीकरण कार्यशाला हो रही है, सभी नगर निकायों के अध्यक्ष वापस जाकर के आप लोग अपने नगर मे पार्षदों के साथ इसी तरह की कार्यशाला करें।

"भारत माता की जय" के गगनभेदी उद्घोष के साथ अपने सारगर्भित और ओजस्वी उद्बोधन में उपमुख्यमंत्री ने नगर निकायों के अध्यक्षों को जहां उनके कर्तव्यों और दायित्वों का बोध कराया ,वहीं उन्होंने उनमें नई ऊर्जा व नए उत्साह का संचार भी किया। उप मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों के विकास और उत्तरोत्तर प्रगति के लिए अपने अनुभव साझा किये ।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप और मुख्यमंत्री मंत्री की मान्शा के अनुरूप नगर निकायों का समग्र और चहुंमुखी विकास करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नगर निकायों के विकास में हमें सबको साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने कहा स्वच्छता को लेकर नगर निकायों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। सभी अध्यक्ष और पार्षद महीने में कम से कम एक दिन अपने नगर क्षेत्र में साफ- सफाई स्वयं झाड़ू लगाकर करें और बिना भेदभाव के विकास करें। नगर निकायों के अध्यक्ष नगर निकाय में कब्जा की गयी जमीनो को मुक्त करायें, लेकिन गरीबों को आवास की व्यवस्था करने के बाद ही उन्हें विस्थापित करें। कहा कि प्रधानमंत्री ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत सरोवर विकसित करने विजन दिया था, और गांव व शहरों में अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, कहा कि हमें अपनी गौरवशाली संस्कृति को संजोए रखने तथा जल संरक्षण के उद्देश्य से अमृत सरोवरो को विकसित करना है, इसलिए शहरों में भी जहां तालाबों में अवैध कब्जे है ,उन्हें खाली कराकर अमृत सरोवरो के रूप में विकसित करें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य गरीबों का कल्याण करना है । नगर निकाय अध्यक्षों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहडी, पटरी दुकानदारों को कर्ज दिलाए व उनके लिए वेंडिंग जोन की स्थापना करायें। उन्होंने कहा कि निकाय मे सड़कों के निर्माण में ओवरलैपिंग ना होने पाए । नगर निकायों के एक-एक पैसे का हिसाब रखना है और यह जिम्मेदारी नगर निकाय अध्यक्षों की है कि वह सजग होकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि गोआश्रय स्थलों पर प्रदत सारी व्यवस्थाएं , सुविधाएं दी जांय। वहां पर गोवंशों का सही तरह से संरक्षण हो। इस बारे में भी नगर निकायों के अध्यक्षों को अपनी नजर रखनी है। उन्होंने कहा कि नगर निकायों के लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। श्री मौर्य ने इस अवसर पर महानगरों के महापौरों को अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया

सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि नये भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाएं : श्री एके शर्मा

नगर विकास मंत्री ने कहा कि नगर किसी देश व प्रदेश का आईना होते हैं। हमारे नगर निवेश के चुम्बक होते हैं। पहले लोग देश के बड़े शहरों बंगलौर, हैदराबाद, बम्बई, सूरत जाते थे लेकिन अब बाहर जाने के जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी नगारिकों को अपने शहरों में ही मूलभुत सुविधाएं मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी निकायों में एक तिहाई अनुपात में महिला प्रतिनिधि जीती हैं। यह हमारे नारी शक्ति के प्रति अच्छी धारणा का प्रतीक है। कहा कि नगरों की बेहतर साफ-सफाई के लिए 50 हजार नियमित सफाई कर्मचारियों के साथ डेढ़ लाख से ज्यादा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लगे हुए हैं ये सभी नगर विकास विभाग परिवार के अंग हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा प्रदेश काफी बड़ा है। प्रदेश की एक तिहाई जनता नगरों में रहती है और हमारे निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि 07 से 08 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सोमवार को निकायों के चेयरमैन व अध्यक्ष 10 बजे

जनसुनवाई करें, मंगलवार को सभी मेयर 10 बजे जनसुनवाई करें। नगरों में शिकायतों के लिए 1533 टोल फ्री नं. की व्यवस्था है, इसे और उपयोगी बनाना है। निकायों के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। आगरा में पेयजल के लिए 264 करोड़ रूपये मंजूर किये गये हैं। श्री शर्मा ने कहा नगर, राज्य की पहचान होते हैं। कोई भी बाहर से जिस नगर में जाता है, वहीं से देखकर प्रदेश के बारे में उसके मन में वैसी ही छवि बनती है। उप्र की लगभग एक तिहाई जनता नगरीय क्षेत्र में निवास करती है, जिसका प्रतिनिधित्व नगर निकायों के अध्यक्ष और पार्षद कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश अगर कोई देश होता तो आबादी के हिसाब से दुनिया का पांचवा देश होता। भारत की अर्थव्यवस्था में 65% हिस्सा नगर क्षेत्र का होता है। नगर ,निवेश के चुंबक होते हैं निवेश आकर्षित करते हैं। हमें प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाना है। 2047 में दुनिया में सबसे शक्तिशाली और विकसित देश भारत को बनाना है। आधुनिक भारत बनाने में नगर निकाय प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

सभी निर्वाचित प्रतिनिधि अपने शहर को बनाएं आदर्श शहर : मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि भारत सरकार के 9 साल के कार्यकाल में सारे सेक्टर में कायाकल्प हुआ है प्रधानमंत्री का विजन देश को विकसित भारत बनाना है ।देश के अमृत काल की प्रथम बेला पर अगले 25 साल में हम ऐसे निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं , जिसमें देश एक नया इतिहास हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, देश का ग्रोथ इंजन बन कर उभर रहा है। इंजन आफ इकोनामिक ग्रोथ शहर होते हैं। शहरों की सेवा करने का अवसर नगर निकाय के प्रतिनिधियों को मिला है। मुख्यमंत्री की संकल्पना के अनुरूप उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। इस ग्रोथ इंजन को ताकत देने वाले नगर निकाय हैं। स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की भी उन्होंने चर्चा की और कहा कि प्रदेश में 15 लाख लोगों को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में अभूतपूर्व कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम सब लोग अपने शहर को आदर्श शहर बनाने की ओर अग्रसर हो। कहा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है उसी प्रकार सभी नगर निकाय अपना फाऊंडेशन डे मनाये।

निकायों के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रत्येक निकाय में हो डाटा के साथ कार्यों का स्पष्ट लेखा-जोखा :उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक

- **नगरों के विकास में आड़े नहीं आयेगी पैसे की कमी**
- **नगरीय व्यवस्थापन, आवश्यक कार्यों के लिए वित्तीय प्रबंधन बहुत आवश्यक**

लखनऊ। प्रदेश के सभी नगर निगमों के नवनिर्वाचित महापौर, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन नगर विकास विभाग द्वारा इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के ज्यूपिटर हॉल में किया गया, जिसमें मा. मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यशाला का तृतीय सत्र उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में नगरीय नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन विषय पर आयोजित की गयी साथ ही नगर विकास विभाग के सलाहकार श्री केशव वर्मा का सिटीज ईज इंजन ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ एण्ड इन्हैंन्सिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ विषय पर व्याख्यान हुआ।
कार्यक्रम के द्वितीय सत्र को सम्बोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की वैश्विक छवि बदली है। पूरी दुनिया में भारत का मान-सम्मान बढ़ा है और दुनियाभर के लोग भारत की ओर देख रहे हैं। कहा कि प्रदेश के नगरीय व्यवस्थापन, साफ-सफाई के कार्य, पार्कों व फुटपाथों के सुन्दरीकरण कर बेहतर नगर बनाना है। प्रदेश के विकास से ही देश का विकास सम्भव है। इसके लिए

उत्तर प्रदेश अगर कोई देश होता तो आबादी के हिसाब से दुनिया का पांचवा देश होता। इतनी बड़ी आबादी के व्यवस्थापन एवं सुख-सुविधा के लिए एकजुट होकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि निकायों के बेहतर प्रबंधन एवं कार्यों की गुणवत्ता के लिए सभी निकायों का अपना डाटा होना जरूरी है। उन्होंने चुनाव जीतने पर सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया और कहा कि चुनाव जीतना कोई साधारण कार्य नहीं। जिसके साथ जनता का दिल मिलता है उसे ही वोट मिलता है। कड़ी मेहनत के बाद यह सफलता मिलती है।
कार्यक्रम के दौरान विभागीय योजनाओं एवं क्रियाकलापों से सम्बंधित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यशाला का प्रथम सत्र नगरीय सुशासन के संवैधानिक एवं विधिक प्राविधानों के सम्बंध में जानकारी देने के लिए आयोजित किया गया।

प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने दी सभी घटकों की जानकारी

लखनऊ। नगर विकास विभाग द्वारा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यशाला में प्रमुख सचिव अमृत अभिजात जी ने मा. जनप्रतिनिधियों को केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं के बारें में जानकारी दी। उन्होंने नगर विकास के संरचनात्मक ढांचे के बारे में बताते हुए कहा कि विभाग मंत्री जी के आदेश पर चलता है, प्रमुख सचिव देखते है, विशेष सचिव रहते है जो खंडो में बंटे होते हैं, उनका कार्यभार अलग-अलग रहता है, कोई विशेष सचिव प्रशासन तंत्र की बात देखता है, कोई स्मार्ट सिटी को देखता है, कोई अमृत को देखता है। इसके अलावा नगर विकास विभाग का दूसरा खंड जल निगम है जिमसें एक डायरेक्ट अफसर मिशन निदेशक के रूप में जल निगम के कार्यों को देखते हैं, जहां से कि मुख्य रूप से राज्य की योजनाएं एवं अमृत मिशन संचालित हो रही हैं। जनपदों से इसकी रूपरेखा डीपीआर के रूप में बन कर आती है। हमारी ये कोशिश है कि 2027 तक सभी नगरों में शत प्रतिशत घरों में पानी देना है जिसके लिए हम सभी कार्यरत है। उन्होंने कहा कि इस प्लानिंग-प्रोसेस में सभी मेयर और नगर पालिका के लोग जो इसमें जुड़े हुए है सबकी एक अहम भूमिका होती है। क्योंकि इसमें भागीदारी सिर्फ जगह से नहीं परंतु शेयर भी अर्बन लोकल बॉडी से आना होता है।
एक जो दूसरा खंड है निदेशालय जिसे नेहा शर्मा हेड करती है। यहां से सारे EOs का इसटेबलिशमेंट, समस्त लोगों का वर्क ऑर्डर

का कंट्रोल होता है, वहां से उनकी पोस्टिंग होती है उनकी ट्रेनिंग होती है। एक तरह से आप मान लें कि वो आपका मठ है जहां से सारा कुछ ज्ञान की बातें, लिट्रेचर अवेलेबल कराना है, शंका दूर करना है, किसी की प्रोसीडिंग के बारे में जानकारी लेनी है, ट्रेनिंग करना है या करवाना है, इसे आप भलीभाति से उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि चंद महीने पहले इसमें कुछ और ट्रेनिंग प्रोग्राम जोड़े गए हैं जिसमें इंजीनियर कैडर के लोग, EOs के लोग हैं, करारोपण के लोग है।
तीसरा घटक है 15th Finance Commision से जो धनराशि प्राप्त होती हैं ये बड़ी मात्रा में आती है, इससे आप एयर क्वालिटी की स्कीम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्कीम, सैनिटेशन की खरीद इत्यादि कर सकते हैं।इसके अलावा अंत्योष्टि स्थल योजना है तथा श्रवानो को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आने वाली है, जिसमें कि हर मण्डल में ABC Center का निर्माण कराया जाएगा, व उसमें उत्तर प्रदेश ऐसी योजना लाने वाला पहला राज्य होगा।

कार्यक्रम की झलकियां

श्री अमृत अभिजात
प्रमुख सचिव नगर विकास
उत्तर प्रदेश

नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण मुद्दा है, जिसके लिए नगर विकास विभाग तत्परता से कार्य कर रहा है। नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या, व्यापार, उद्योग, परिवहन आदि के कारण भूमि का उपयोग अधिक होता है और यहां बड़ी मात्रा में अपशिष्ट, कचरा, प्लास्टिक, और अन्य कचरे का उत्पादन होता है। स्वच्छता की समस्याओं से निपटने के लिए कचरे के संगठन और नियंत्रण का प्रबंधन पर निरंतर कार्य हो रहा है। नवाचारी तकनीकों का उपयोग करके शहरों को अधिक स्वच्छ और उनके विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए अभियानों और जनता के सहयोग के साथ मिलकर जागरूकता का कार्य हो रहा है। स्वच्छ और सुंदर नगरीय क्षेत्र न सिर्फ स्थानीय निवासियों के लिए अच्छा होता है, बल्कि इससे पर्यटकों का भी आकर्षण होता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहित करता है।

विश्व पर्यावरण दिवस

प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से युक्त वातावरण में बदलाव के लिए पौधे जरूर लगाएं : नेहा शर्मा

- **प्रत्येक नागरिक को कम से एक पौधा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अपने जीवन में अवश्य लगाना चाहिए**
- **नेहा शर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलायी**

लखनऊ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर निदेशक नगरीय निकाय ने निदेशालय परिसर में आम और कटहल का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर तत्कालीन निदेशक नेहा शर्मा ने कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सभी नागरिकों और आम जनमानस से अपील करना चाहूंगी कि इस महत्वपूर्ण दिवस को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने आसपास एक पौधा जरूर रोपित करना चाहिए। आगे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने का यह कार्य आज की वर्तमान पीढ़ी द्वारा किया जाना बहुत आवश्यक है। प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वन और पर्यावरण संरक्षण की जो मुहिम चलाई है,उसमें हम सब पौधरोपण करके अपना योगदान दे सकते हैं। श्रीमती नेहा शर्मा ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को पर्यावरण के संरक्षण की भी शपथ दिलायी। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी देखभाल भी जरूरी है। पौधों का पूर्ण संरक्षण आवश्यक है। तभी वे हम सभी के लिए उपयोगी साबित होंगे और हम भी स्वस्थ रहेंगे।

श्रीमती नेहा शर्मा ने कहा कि प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से युक्त वातावरण में सकारात्मक बदलावों को लाने के लिए देश के नागरिक के रुप में किसी भी देश के युवा सबसे बड़ी उम्मीद है। प्रत्येक नागरिक को कम से एक पौधा अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अपने जीवन में अवश्य लगाना चाहिए।

ट्यूलिप (शहरी शिक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम)

MoHUA द्वारा शुरू किया गया जो की एक नया और अनोखा शिक्षण मंच है जिसके अन्तर्गत नए प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पर रखा जाता है और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में सीखने और काम करने के लिए तैयार किया जाता है। ट्यूलिप कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षुओं को सरीकारी योजनाओं के विषय में जानकारी मिलने के साथ साथ सरीकारी योजनाओं में काम करने का अनुभव भी प्राप्त होता है "ट्यूलिप " के तहत उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर कुल 3742 में से सबसे अधिक 1166 प्रशिक्षुओं ने प्रतिभाग किया है। इन 1166 ट्यूलिप इंटर्नशिप में से 123 अब तक पूर्ण हो चुकी हैं और 1143 जारी हैं। ट्यूलिप कार्यक्रम के तहत, हमें विभिन्न क्षेत्रों से प्रशिक्षु मिले हैं और उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन (यू) के विभिन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान दिया है।

एसबीएम शहरी, उत्तर प्रदेश ने ट्यूलिप प्रशिक्षुओंका उपयोग ज्यादातर आरआरआर केंद्र चलाने और उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से जान सामान्य को स्वच्छ भारत मिशन के विषय में जागरूक करने में किया गया है। भविष्य में "ट्यूलिप" कार्यक्रम को और भी वृहद् स्तर पर चलाये जाने की योजना है।

बरसात में कहीं पर भी जल भराव की समस्या न हो : नगर विकास मंत्री

- **नगर विकास मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने की निकाय कार्यो की समीक्षा**

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने सभी निकाय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी है कि अपने निकायों में नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने तथा व्यवस्थापन पर विशेष ध्यान देंगे। साथ ही बरसात में कहीं पर भी जल भराव की समस्या न हो। इसके लिए 15 जून से पहले सभी नाले, नालियों की साफ-सफाई सुनिश्चित करा लें। उन्होंने जल भराव वाले स्थानों को अभी से चिन्हित करने तथा ऐसे स्थानों में जल निकासी के लिए पम्पों की पर्याप्त व्यवस्था हो और सभी पम्प चालू स्थिति में हों। नागरिकों को तकलीफ से बचाने और एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने निर्देशित किया कि सभी निकाय अधिकारी फील्ड में जाकर कार्यों की जमीनी हकीकत देखेगे। नगर विकास मंत्री ने सभी 762 नगरीय निकायों में बरसात से पहले नाले व नालियों की सफाई, जल भराव वाले स्थानों का चिन्हीकरण, पेयजल आपूर्ति, दैनिक सफाई की व्यवस्था, संचारी रोगों के रोकथाम के लिए फागिंग, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन आदि कार्यों की वर्चुअल समीक्षा की। उन्होंने नाले नालियों की सफाई कार्यों पर हो रही लेटलतीफी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि

अभी तक सफाई का 50 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ। कहीं-कहीं पर तो 20 से 30 प्रतिशत तक ही सफाई का कार्य हुआ है। बरसात के दौरान शहरों में कहीं पर भी जल भराव की स्थित न बने, जिससे कि नागरिको को परेशानी हो। इसके लिए सभी नाले नालियों की तलछट सिल्ट सफाई, इन पर उगी झाड़ी-झाड़ियों एवं प्लास्टिक व पालीथीन की सफाई सुनिश्चित करें। सभी चोकिंग प्वाइन्ट को चिन्हित कर उचित प्रबंध किया जाए। श्री ए0के0 शर्मा ने सभी अधिकारियों को संबंधित एजेंसियों एवं विभागों के साथ बैठक करने और समस्याओं के समाधान के लिए वृहद कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निकाय के अधिकारियों के कार्यों के आधार पर ही उनका मूल्यांकन किया जायेगा।

जी-20 की बैठकों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त हुआ वाराणसी

- **नगर विकास एवं सम्बंधित विभाग के समन्वय काशी बनी और भी दिव्य और भव्य : नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा**

लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने 11 जून, 2023 से वाराणसी में जी-20 से सम्बंधित बैठकों को लेकर नगर विकास, ऊर्जा एवं अन्य विभागों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, इस दौरान एक बार फिर से प्रदेश की संस्कृति व ऐतिहासिक धरोहर एवं हमारे शहरों के व्यवस्थापन, सुन्दरता को निहारने के लिए विदेशी मेहमान आएंगे। उन्होंने कहा कि इसके पहले आगरा एवं लखनऊ में हुए जी-20 की बैठकों तथा लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान आये विदेशी मेहमानों ने शहरों की सुन्दरता, भव्यता और बेहतर व्यवस्था की प्रशंसा की। इससे हमारे देश व प्रदेश की वैश्विक छवि बदली।
नगर विकास मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होने वाले जी-20 की बैठकों से प्रदेश की छवि और निखरेगी, जिसका लाभ आगामी वर्षों में देखने को मिलेगा। कहा कि प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों के बाद भोलेनाथ की काशी और भव्य व दिव्य दिखने लगी है। जी-20 के सम्मेलनों की दृष्टि से मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विदेशी मेहमानों के स्वागत-सत्कार में कहीं कमी न रह जाये

इसके लिए वाराणसी शहर की साफ-सफाई, सुशोभन, सुन्दरीकरण, बेहतर व्यवस्थापन, सजावट व लाइटिंग पर विशेष जोर दिया गया है। शहर की गलियों, चौराहों, फुटपाथों की साफ-सफाई के साथ शहर की हरियाली बढ़ाने के लिए गमले रखना और गार्डेन बनाने के निर्देश दिये गये हैं।

श्री ए0के0 शर्मा ने बताया कि वाराणसी शहर के बेहतर व्यवस्थापन, साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, मार्ग प्रकाश आदि कार्यों की व्यवस्था को बेहतरीन ढंग से संचालित करने के लिए अन्य निकायों से कार्मिकों एवं उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए नगर आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिये गये थे। इसमें नगर निगम लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर तथा नगरपालिका परिषदों में गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर व पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर (चंदौली) शामिल हैं, जिसमें से कुल 385 कार्मिक एवं जरूरी उपकरण उपलब्ध कराये गये। इसमें नगर निगमों से 02 अधिशासी अभियंता (सिविल), 25 अवर अभियंता (सिविल), 03 जोनल स्वच्छता अधिकारी, 05 अवर अभियंता/सहायक अभियंता, 13 वर्क सुपरवाइजर, 20 लाइनमैन, 29 हेल्पर, जलकल से 04 अधिशासी अभियंता, 09 सहायक अभियंता, 17 अवर अभियंता हैं। प्रयागराज नगर निगम से 05 बड़ी एलईडी स्क्रीन, 02 मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीन, 03 हजार बड़े गमले भेजे गये हैं। 27 छोटी-बड़ी लैडर/स्काई लिफ्ट भी उपलब्ध करायी गयी हैं। इसी प्रकार उक्त नगरपालिका परिषदों से 04 अवर अभियंता (सिविल), 200 सफाईकर्मी, 20 सफाई सुपरवाइजर, 04 सफाई एवं खाद्य निरीक्षक भेजे गये हैं। 08 छोटी-बड़ी लैडर/ स्काई लिफ्ट, 07 डम्फर, 07 ट्रेक्टर, 07 जेसीबी, 09 स्प्रीन्कलर, 04 टैंकर मय ट्रेक्टर एवं स्प्रीन्कलर भेजे गये हैं।

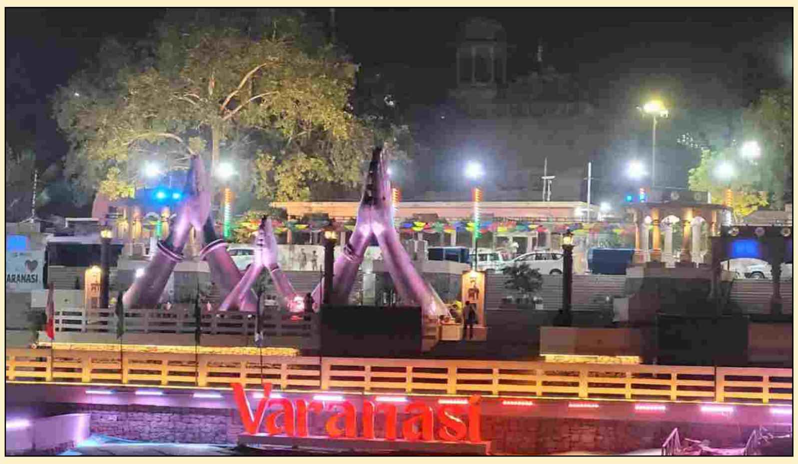

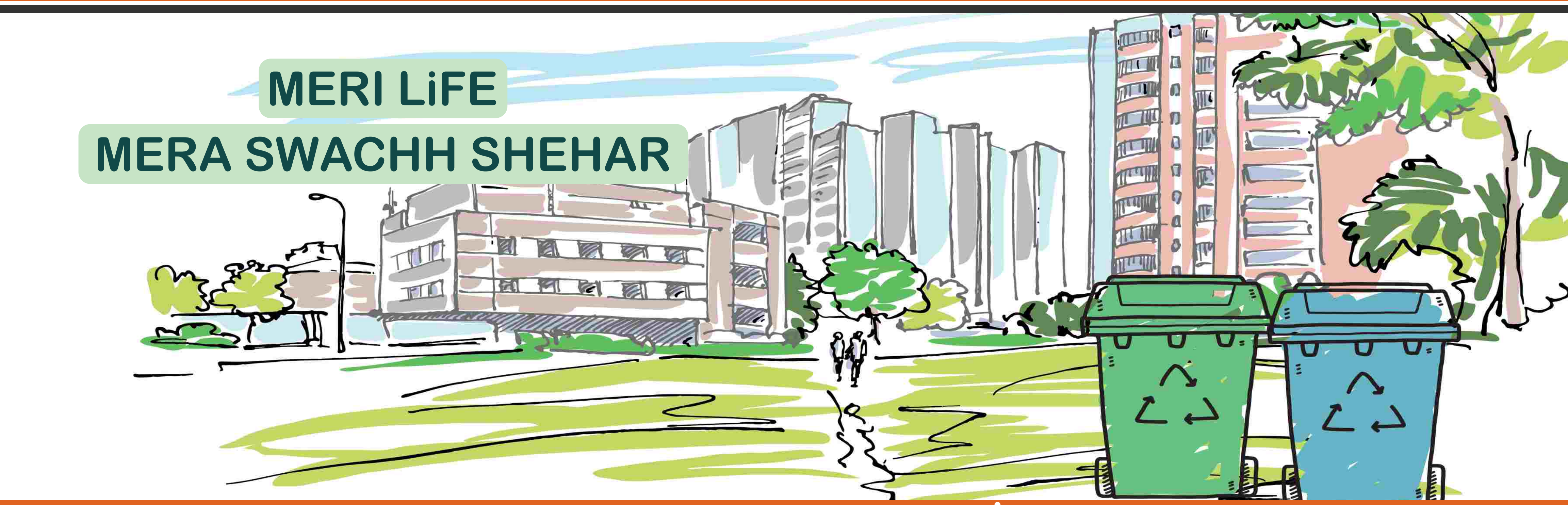

निकायों द्वारा श्रेयस्कर गतिविधियाँ

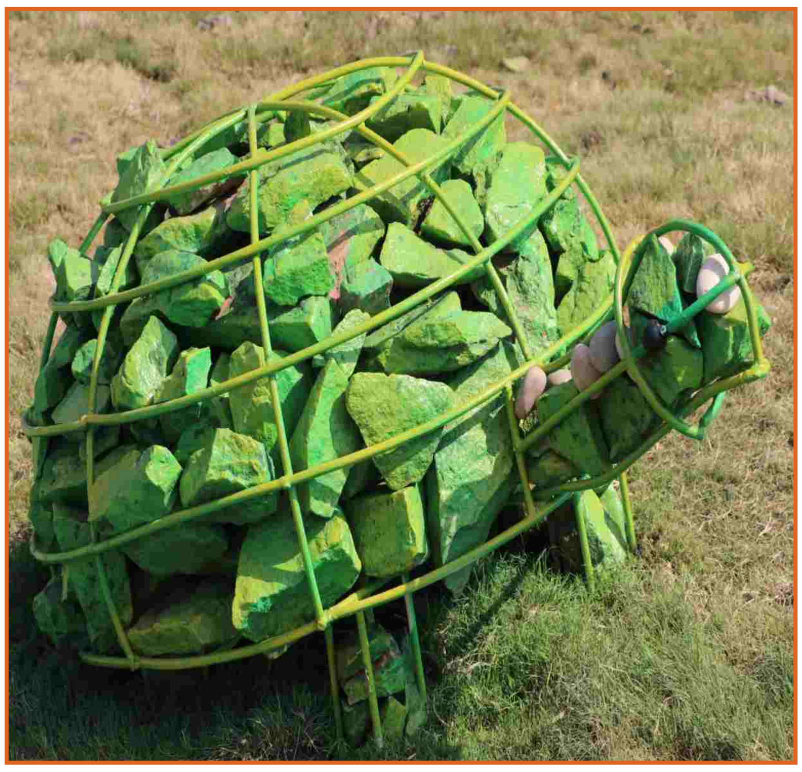

निदेशक की कलम से...

श्री नितिन बंसल
निदेशक, स्थानीय निकाय
उत्तर प्रदेश

स्वच्छ शहर के निर्माण में जन जागरूकता एक महत्वपूर्ण साधन है। जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को स्वच्छता में शामिल किया जा रहा है। लोगों को शहर की स्वच्छता के महत्व को समझाने और साझा करने के लिए समुदायिक सभायें और जागरूकता अभियान लगातार चलाये जा रहे हैं। स्वच्छता के लिए लोगों को शिक्षित और सचेत भी किया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाये जा रहे हैं। संचार माध्यमों का उपयोग करके स्वच्छता संदेशों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। शहर की सड़कों और गलियों की सफाई के लिए सुबह 5 बजे से ही सफाई मित्र तत्परता से अपने कार्यों में जुट जाते हैं, जिसकी वर्चुअल मॉनिटरिंग भी डीसीसीसी के माध्यम से लगातार की जा रही है। सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था के लिए जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को सार्वजनिक शौचालयों और ट्विन -बिन का महत्व भी बताया जा रहा है। साथ ही जन जागरूकता को संगठित और संवेदनशील तरीके से संचालित कर स्वच्छ शहर के लिए जनसाधारण का सहयोग लेकर एक सकारात्मक परिवर्तन लाया जा रहा है।

सभी निकाय बरसात से पहले युद्ध स्तर पर पूरा कराएं नाले नालियों का सफ़ाई कार्य : ए के शर्मा

- **मैनपॉवर, मशीनों व उपकरणों का सही से प्रयोग कर समय रहते व्यवस्था को पूर्ण रूप से सुधारे**
- **सुबह 05:00 से 08:00 बजे के बीच होने वाली नियमित साफ-सफाई में कही पर भी ढ़िलाई न बरती जाए**
- **शिकायतों की सुनवाई हेतु उपलब्ध टोल फ्री नं0-1533 की व्यवस्था को सभी निकायों में करें संचालित**

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने कहा कि सभी निकाय बरसात से पहले अपने यहाँ के नाले नालियों की सफ़ाई कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा कराएं, जहाँ कहीं पर भी नाले नालियों के निर्माण में तकनीकी ख़ामिया या चोक होने की समस्या हो, उसे भी शीघ्र ही ठीक कराया जाए, जिससे कि बरसात के दौरान कहीं पर भी जल निकासी में समस्या न हो तथा लोगों को जल भराव का सामना न करना पड़े। इसके लिए मैनपॉवर, मशीनों व उपकरणों का सही से प्रयोग कर समय रहते व्यवस्था को पूर्ण रूप से सुधारे। सभी निकाय अपने आस पास की निकायों से बेहतर तालमेल बनाकर संसाधनों का सही से उपयोग करें। ज़रूरत पड़ने पर आपस में मदद भी करें। मंत्री श्री शर्मा ने वर्चुअल समीक्षा की और साफ-सफाई को

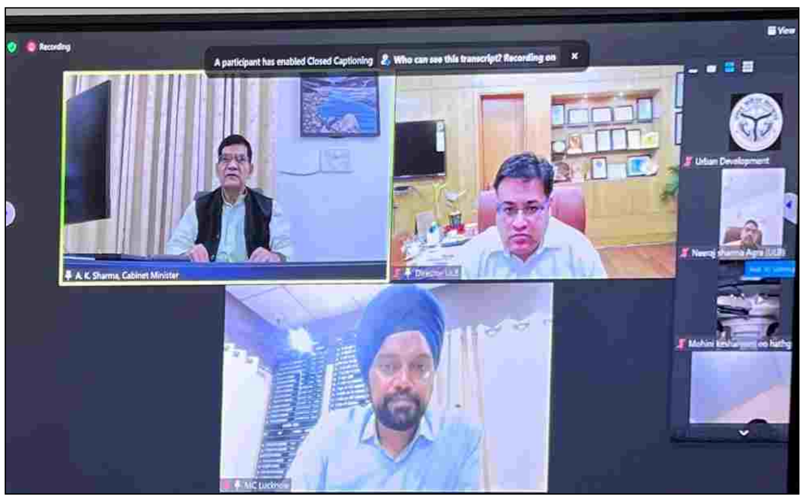

लेकर जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सभी 762 निकायों में सुबह 5 से 8 बजे के बीच होने वाली नियमित साफ-सफाई में कही पर भी ढ़िलाई न बरती जाए। नवगठित व नवविस्तारित निकायों में विकास कार्यों को प्रमुखता से कराया जाए। विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों को समय से मिले, इसके प्रयास किए जाए। उन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष में कराये जाने वाले कार्यों से संबंधित प्रस्ताव को शीघ्र निकाय निदेशालय में भेजने को कहा। शहरों में विकास कार्यों के लिए पैसे की कमी नही है। उन्होंने निकाय निदेशक श्री नितिन बंसल को निर्देश दिये कि डीसीसीसी के माध्यम से निकाय कार्यों की, की जा रही मानीटरिंग की निगरानी करें तथा विगत एक सप्ताह के कार्यों की रिपोर्ट भी निकायों से मगायें। उन्होंने कहा कि अभी वाराणसी में हुई जी-20 की बैठकों में नगर निगम द्वारा की गई तैयारियों, व्यवस्थापन, सुन्दरीकरण के कार्यों की अन्तराष्ट्रीय प्रतिभागियों ने प्रशंसा की। बहुत ही कम समय में नजदीकी अन्य निकायों के सहयोग से वाराणसी शहर को सुंदर बनाया गया। इसी प्रकार सभी निकाय समन्वय बनाकर कार्य करें। श्री शर्मा ने लोगों की शिकायतों की सुनवाई हेतु उपलब्ध टोल फ्री नं0-1533 को निकायों में संचालित करने के निर्देश दिए।

कुशीनगर : नगर विकास मंत्री ने नगर पंचायत फाजिलनगर के नवनिर्मित कार्यालय भवन का किया उद्घाटन

- **158.43 लाख की लागत से हुआ कार्यालय का निर्माण**

लखनऊ/कुशीनगर। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने कुशीनगर जनपद की नवसृजित नगर पंचायत फाजिलनगर के नवनिर्मित कार्यालय भवन का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए कहा, इस कार्यालय भवन का निर्माण 158.43 लाख रूपये की लागत से सीएनडीएस कार्यदायी संस्था द्वारा कराया गया। 23 दिसम्बर, 2019 को फाजिलनगर नाम से यह नई नगर पंचायत बनी, जिसमें 15 वार्ड हैं। जिसमें 09 गॉव शामिल किये गये हैं और इस नगर पंचायत की वर्तमान में आबादी लगभग 25 हजार के आसपास है। नगर विकास मंत्री ने कहा कि फाजिलनगर की जनता को जल्द से जल्द नगरीय सुविधायें मिले और उस क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हो, इसके लिए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया गया है। कोई भी कार्यालय किसी व्यवस्था को संचालित करने का केन्द्र होता है। बेहतर व्यवस्था प्रदान करने के लिए कार्यालय में आधुनिक सुविधायें हों, जिससे जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने फाजिलनगर नगर पंचायत के चेयरमैन श्री शत्रुमर्दन प्रताप शाही से कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए इससे संबंधित प्रस्ताव बनाकर शीघ्र ही

निदेशालय को भेजा जाए, जिससे कि धनराशि दी जा सके। विकास कार्यों के लिए पैसे की कमी नहीं है।
श्री शर्मा ने कहा कि नवसृजित नगर पंचायत में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत विभिन्न विकास कार्य कराये जाने हैं। इसके अलावा क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट, शादी के लिए कल्याण मण्डपम, जल निकासी, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास, नाली, खडंजा का निर्माण, सड़क निर्माण, तालाब पार्कों का निर्माण, कान्हा गौशाला आदि कार्यों के लिए पैसे हैं। ऐसे नगरों में बिजली की व्यवस्था के लिए 01 हजार करोड़ रूपये की धनराशि कि व्यवस्था है। इसके माध्यम से बांस बल्ली को हटाकर पोल लगाना, विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु आरडीएसएस योजना के तहत कार्य किया जाना है।

आरंभ 2.0 (ARAMBH 2.0)

A- Awareness, R-Refuse, A-Alternative of Plastic, M- Mass Campaign, B-Be Responsible, H-Hammer to Single use Plastic

पर्यावरण वन और जल वायु प्रवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त 2021 के तहत 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक की रोकथाम हेतु प्रदेश में आरंभ 2.0 (जून 2023) के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए सभी निकायों में अलग-अलग गतिविधियां चला कर लोगों को जागरूक कर प्लास्टिक जब्त कर फाइन भी लगाया गया है, जिसके तहत लोगों में जागरूकता भी पैदा हुई है। साथ ही जूट के बने थैले के उपयोग को भी बढ़ावा दिया गया। 2.0 के तहत 33090 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त की गई और उल्लंघनकर्ताओं पर ₹ 4191615.00 जुर्माना लगाया गया है।

आगरा : नगर विकास मंत्री ने सर्किट हाउस में की समीक्षा बैठक

- **युद्धस्तर पर सभी नालों की सफाई कराना सुनिश्चित करे नगर निगम : एके शर्मा**
- **जी-20 के दौरान नगर की हुई साफ सफ़ाई, सुंदरीकरण को बनाए रखा जाय, गड़बड़ी पर होगी सख्त कारवाई : एके शर्मा**
- **शहर का कोई क्षेत्र गंगाजल से न रहे वंचित : नगर विकास मंत्री**
- **जिले में गौशलाओं के लिये बनवायी जाए डिस्पेंसरी : एके शर्मा**

लखनऊ/आगरा। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा अपने एक दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे। आगरा के प्रभारी मंत्री श्री शर्मा ने शासन द्वारा आगरा में संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कहीं पर भी साफ़ सफ़ाई का कार्य रह गया हों, तो युद्धस्तर पर लगकर मानव मशीन का अधिक से अधिक उपयोग कर समय से सभी नाले-नालियों की साफ-सफाई का कार्य संपन्न कर लिया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जी-20 के समय जो विकास कार्य कराए गए हैं, नगर की साफ सफ़ाई, सुंदरीकरण का जो कार्य किया गया है, उसे बनाए रखें,क्षतिग्रस्त होने से बचाएं, नहीं तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का समय से व गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण कराएं। आगरा शहर प्राचीन काल से ही उद्योग प्रधान रहा है, यहां उद्योग की बहुत संभावनाएं हैं। पेयजल आपूर्ति हेतु शहर के समस्त क्षेत्रों में गंगाजल न पहुंचने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने

समस्त क्षेत्रों में गंगाजल आपूर्ति कराने के निर्देश दिए। मंत्री जी ने गौशलाओं के लिये डिस्पेंसरी बनवाने तथा सरकार की विकास परक योजनाओं को माह दिसम्बर तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त श्री प्रीतिन्दर सिंह, जिलाधिकारी श्री नवनीत सिंह चहल, नगर आयुक्त श्री अंकित खण्डेलवाल, उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण श्री चर्चित गौड़, मुख्य विकास अधिकारी श्री ए. मनिकन्डन, परियोजना निदेशक श्रीमती रेनू कुमारी, मुख्य चिकित्साधिकारी श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मऊ : नगर विकास मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने मऊ में 408.50 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण

- प्रदेश के चहुमुखी विकास कार्यों का आमजन को मिल रहा लाभ
- बिना भेदभाव के योजनाओं को ज़मीन पर उतारा जा रहा : श्री ए.के. शर्मा

लखनऊ/मऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं उर्जा मंत्री श्री ए०के० शर्मा द्वारा मऊ जनपद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना अंतर्गत स्ट्रीट लाइट सम्बंधी 03 विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया, जिनकी कुल लागत 408.50 लाख रुपए है। सर्वप्रथम मंत्री जी द्वारा गाजीपुर तिराहा से आजमगढ़ मोड़ तक तथा साबरी मस्जिद से मिर्जाहादीपुरा चौक तक 09 मीटर लंबे गैल्वेनाइज्ड पोल को लगाकर डबल आर्म एलईडी लाइट अधिष्ठान कार्य का शुभारंभ किया गया, जिसकी कुल लागत 156.56 लाख रुपए है। इसके उपरांत मंत्री जी ने मिर्जाहादीपुरा चौक से हकीकतपुर पालिका सीमा तक 09 मीटर लंबे गैल्वेनाइज्ड पोल लगाकर डबल आर्म एलईडी लाइट अधिष्ठापन कार्य का भी शुभारंभ किया। इस परियोजना की कुल लागत 121.89 लाख रुपए है।

इसी क्रम में नगर पालिका में विस्तारित क्षेत्र अमारी पुलिया से बड़ागांव होते हुए पूर्व पालिका सीमा तक 09 मीटर लंबे गैल्वेनाइज्ड पोल लगाकर डबल एलईडी अधिष्ठापन कार्य का शुभारंभ हुआ, जिसकी कुल लागत 130.04 लाख रुपए है। इस दौरान मंत्री जी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का कार्य कर रही, प्रदेश के चहुमुखी विकास का लाभ आमजन को मिल रहा है। बिना भेदभाव के योजनाओं को ज़मीन पर उतारा जा रहा। मंत्री जी के लोकार्पण कार्यों के दौरान मऊ जनपद के जिलाधिकारी अरुण कुमार, पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पशु चिकित्सकों की देखरेख में डॉग केयर सेंटर में ऐसे श्वानों का इलाज किया जायेगा : प्रमुख सचिव अमृत अभिजात

विक्षिप्त व हिंसक व्यवहार वाले श्वानों को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक ए.बी.सी. सेण्टर में डॉग केयर सेंटर की होगी स्थापना

- हिंसक व्यवहार करने वाले श्वानों को डॉग केयर सेंटर में रखा जायेगा

लखनऊ। प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अभिजात ने कहा कि प्रदेश में श्वानों की संख्या को वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधित करने के लिए प्रत्येक नगर निगम में एक ए.बी.सी. सेण्टर की स्थापना की जा रही है। लखनऊ और कानपुर नगर निगम में ए.बी.सी. सेन्टर बनाये जा चुके हैं। इन सभी ए.बी.सी. सेन्टर में विक्षिप्त व हिंसक व्यवहार वाले श्वानों को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक ए.बी.सी. सेण्टर के अन्तर्गत एक डॉग केयर सेंटर की भी स्थापना की जा रही है। इस संबंध में प्रदेश के समस्त नगर आयुक्तों को निर्देश भी दिये गये हैं। प्रमुख सचिव ने बताया कि आक्रामक रूप से काटने वाले विक्षिप्त व हिंसक व्यवहार करने वाले श्वानों को ए.बी.सी. सेंटर के अन्तर्गत स्थापित डॉग केयर सेंटर में ही रखा जायेगा। इसके लिए डॉग केयर सेंटर के संचालन हेतु पोर्टल एवं हेल्पलाइन, शिकायत नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना के साथ-साथ डाटा का रख-रखाव भी किया जायेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे श्वानों की शिकायत प्राप्त होने पर प्रशिक्षित डॉग हैंडलिंग टीम द्वारा मानवीय रूप से पशु क्रूरता अधिनियम 1960

के प्राविधानों का कड़ाई से पालन करते हुए डॉग पकड़कर डॉग केयर सेंटर लाया जायेगा, जहाँ पर पशुचिकित्सकों के पैनल द्वारा 10 दिन तक ए.बी.सी. सेंटर में रखकर उनका निरीक्षण किया जायेगा।
जांचोपरान्त श्वान में रेबीज नहीं पाये जाने पर उसके मूल स्थान पर छोड़ दिया जायेगा। श्वान में रेबीज के लक्षण पाये जाने की स्थिति में ऐसे श्वानों का 02 सदस्यीय पैनल द्वारा अनिवार्य रूप से 03 सप्ताह तक निरीक्षण किया जायेगा। 03 सप्ताह के निरीक्षण/उपचार के उपरांत यदि श्वान पूर्णतया स्वस्थ हो जाते हैं, तो ऐसे श्वानों को उनके मूल स्थान पर छोड़ दिया जायेगा। यदि 03 सप्ताह के पश्चात भी श्वान में किसी प्रकार के संचारी/गंभीर रोग के लक्षण बने रहते है, तो उन्हें पशु चिकित्सकों की देखरेख में डॉग केयर सेंटर के आइसोलेशन केनल में रखा जायेगा और प्रत्येक 02 माह के अन्तराल पर पैनल द्वारा निरन्तर निरीक्षण किया जायेगा। श्वानों में रेबीज होने की उच्च संभावना पाये जाने पर उसे अलग केनेल में रखा जायेगा। श्वानों के निरंतर अवलोकन और मूल्यांकन के बाद भी यदि श्वान में बिना उकसावे के काटने की आदत पायी जाती है, तो उसे डॉग केयर सेंटर से वापस नहीं छोड़ा जायेगा।

स्वच्छ त्योहार : सभी नगरों एवं पूजा स्थलों की साफ-सफाई सुनिश्चित करायी जाए

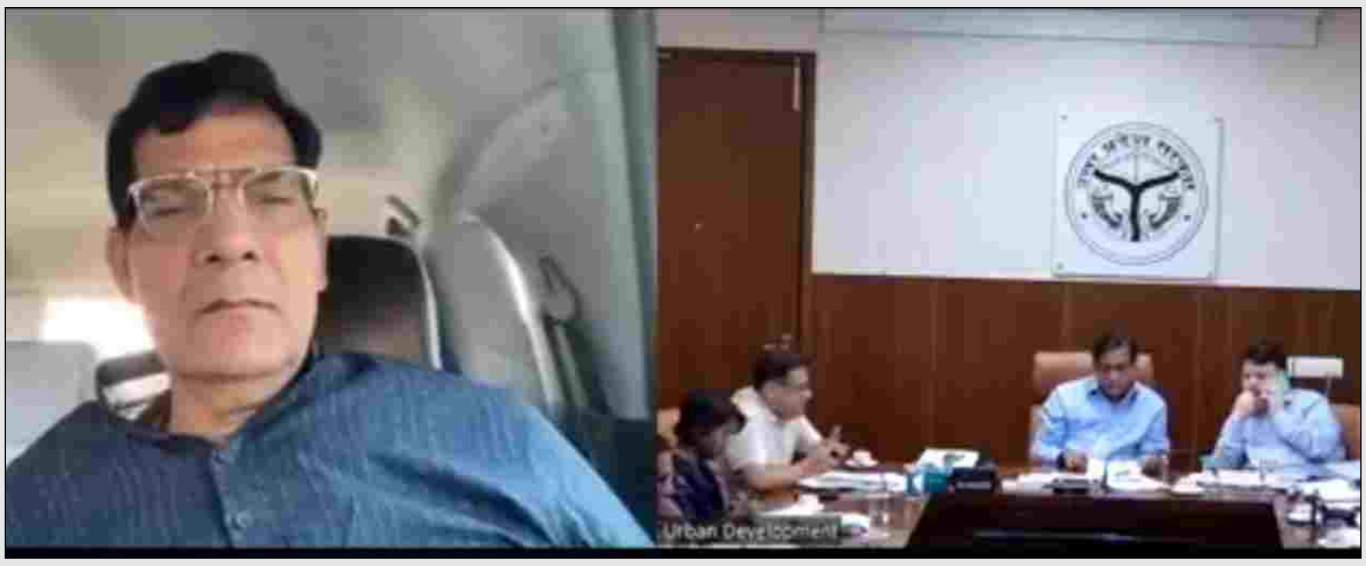

- बकरीद के त्योहार के दौरान कुर्बानी के अवशेषों का शीघ्र निस्तारण किया जाए : एके शर्मा

लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए0के0 शर्मा ने कहा कि आने वाले त्योहारों के दृष्टिगत सभी नगरों एवं पूजा स्थलों की साफ-सफाई सुनिश्चित करायी जाए। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, आश्रय स्थल, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था भी करायी जाए। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में कांवड़ यात्रा, मेलों का आयोजन, नागपंचमी, रक्षाबन्धन आदि त्योहारों के दौरान धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायी जाएं। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में मेलों, त्योहारों को साफ एवं स्वच्छतापूर्ण ढंग से मनाये जाने का प्रबंध किया जाए है। बकरीद के त्योहार के दौरान कुर्बानी के अवशेषों का शीघ्र निस्तारण किया जाए, जिससे आमजन को परेशानी न हो। त्योहारों में साफ-सफाई के प्रति लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री श्री शर्मा ने प्रमुख सचिव नगर विकास को निर्देशित किया है कि सभी निकायों में विकास कार्यों का एजेंडा बनाकर लागू करायें। जनता को विकास कार्यों का लाभ बेहतर तरीके से मिले, इसके प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि निकायों का पैसा जनता की सेवा व कार्यों में लगे, पैसों की अनावश्यक बर्बादी न हो, इसके लिए बरसात के समय सड़क एवं नाले-नाली बनाने के लिए जारी किए जा रहे टेण्डर को रोकें। निकाय अधिकारियों के बेहतर परफार्मेंस एवं कार्यों से प्रदेश के शहरों की छवि बदलेगी। शहरों में विश्वस्तरीय व्यवस्था के साथ साफ-सफाई, सुन्दरीकरण पर विशेष जोर हो। शहरों की स्ट्रीट लाइट को व्यवस्थित किया जाए, सालिडवेस्ड मैनेजमेंट, गलियों, मोहल्लों, नाले व नालियों की साफ-सफाई पर ध्यान दिया जाए। नगरों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के लिए मैन-मशीन दोनों का बेहतर उपयोग किया जाए। निकायों में कार्य करने वाली कार्यदायी संस्थाओं एवं एजेंसियों के कार्यों की भी नियमित मॉनीटरिंग की जाए। श्री शर्मा ने वन महोत्सव के दौरान निकायों में पौध रोपण पर विशेष जोर देने को कहा। इसके लिए उन्होंने निकायों की खाली जगहों, साफ किए गए कूड़ा स्थलों, सड़क किनारे की खाली जगहों पर पौध रोपण को कहा। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि वनीकरण के दौरान जितने पौधे लगाये जाएं उनको बेहतर ढंग से संरक्षित भी किया जाए। जहां संभव हो सके मियांवाकी तकनीक का प्रयोग कर पार्क व उद्यान भी बनाएं जाएं। उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण-2023 में निकायों की बेहतर रैंकिंग के लिए सभी अधिकारियों को प्रयास करने को कहा। इसके लिए कूड़ा कलेक्शन, सोर्स सेग्रीगेशन, साफ-सफाई, सुन्दरीकरण आदि कार्यों पर विशेष ध्यान दें। जिन निकायों का कार्य अच्छा नहीं है, उन्हें सचेत भी करें।

दिनांक:21 जून, 2023 को समस्त नगरीय निकायों में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया

लखनऊ/आगरा। नवम अंतराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आगरा के एकलव्य स्टेडियम में "वसुधैव कुटुम्बकम् के लिये योग" थीम के साथ भव्य योगाभ्यास हुआ। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री व आगरा जिले के प्रभारी मंत्री श्री एके शर्मा जी ने जिले में सामूहिक योगाभ्यास किया। इस दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री एस पी सिंह बघेल जी भी मौजूद रहे। योगाभ्यास के उपरान्त मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि योग हमारे देश, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति की अनुपम धरोहर है। बहुत दिनों तक इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होने से यह हमारा पुराना ज्ञान और विधा विलुप्त होती जा रही थी। प्रत्येक वर्ष की भॉति इस वर्ष भी दिनांक 21 जून, 2023 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर "वसुधैव कुटुम्बकम् के लिये योग" विषय के रूप में समस्त नगरीय निकायों मनाया गया और निकाय की परिधि में स्थित समस्त (RWA/NGO,CSO,UNIVERSITY,COLLEGES, SCHOOL) आदि संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर उक्त कार्यक्रम में अपने निकाय के समस्त अधिकारी, कर्मचारी व सफाई मित्रों द्वारा प्रतिभाग किया गया है।

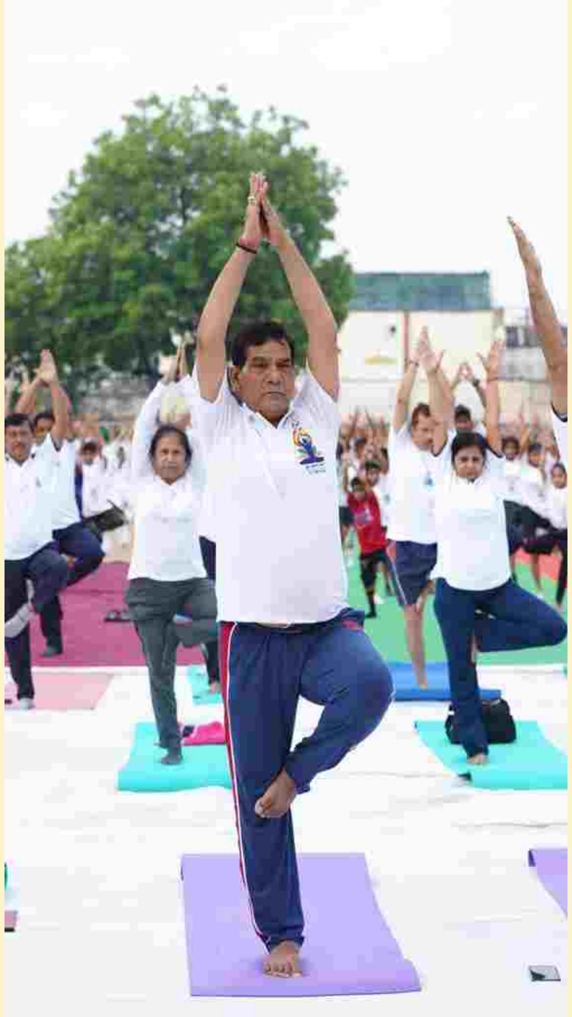

मलिन बस्तियों में मिलेंगी सभी शहरी सुविधाएं, तैयार हो रही स्लम रिडेवलपमेंट पॉलिसी

लखनऊ। राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) ने करीब दो साल पहले "स्लम रिडेवलपमेंट पॉलिसी" का ड्राफ्ट तैयार किया था लेकिन उसमें कई संशोधन किए जाने थे, जो अभी तक नहीं हो पाए हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री की बैठक में इस पॉलिसी की चर्चा हुई तो उन्होंने पॉलिसी में कुछ जरूरी संशोधन के साथ इसे जल्द तैयार कर लागू करने का निर्देश दिया था। इसी कड़ी में नगर विकास विभाग के अधिकारी फिर से पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं।

प्रस्तावित पॉलिसी के तहत मलिन बस्तियों के विकास के लिए दो तरह के विकल्प रखे गए हैं। एक तो नगर निकायों द्वारा और दूसरा विकास प्राधिकरणों के जरिये भी विकास किया जाएगा। पॉलिसी में मलिन बस्तियों का विकास "इन-सीटू स्लम रिडवलपमेंट" (आईएसएसआर) के आधार पर किया जाएगा। यानी जो बस्ती जिस भूमि पर बसी है, उसका विकास वहीं पर किया जाएगा। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को जहां हवादार मकान मिल सकेंगे। वहीं सड़क, सीवर, शुद्ध पेयजल, बिजली, स्ट्रीट लाइट जैसी शहरी सुविधाएं भी मुहैया हो सकेंगी।

आजीविका व प्रशिक्षण केंद्र का भी प्रावधान

पॉलिसी का ड्राफ्ट सभी स्टेकहोल्डर आवास बंधु, आरसीयूइएस, डेवलपर्स, विकास प्राधिकरणों, उप्र आवास विकास परिषद, नगर नियोजन आदि से सुझाव लेकर तैयार किया जा रहा है। इसमें मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए आजीविका केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, पार्क आदि बनाने का भी प्रावधान किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ड्रॉफ्ट तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री के सामने इसका प्रजेंटेशन किया जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी।

पीएम सुनिधि योजना : ऋण देने और डिजिटल पेमेंट में यूपी अव्वल

लखनऊ। कोरोना कालखंड के दौरान बेरोजगार हुए पटरी दुकानदारों को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम सुनिधि योजना की शुरुआत की थी। जिसके तहत पटरी दुकानदारों को ऋण वितरित किये गए थे। प्रदेश सरकार की सतत निगरानी में हुए ऋण वितरण में यूपी देश का अव्वल राज्य बन गया है। केंद्र सरकार के स्तर पर कराई गई रैंकिंग के मुताबिक पीएम स्वनिधि के अलावा सात अन्य केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भी यूपी ने दूसरे प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया है। पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत पटरी व्यवसायियों को 1 साल तक के लिए 10 से 50000 तक का ब्याजमुक्त ऋण दिया गया था। राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के निदेशक डॉ अनिल कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं इन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश ने पीएम सुनिधि समेत कुल 8 केंद्रीय योजनाओं का लाभ देने में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश में अब तक 9,57,771 लाभार्थी पहली, 2,29,014 लाभार्थी दूसरी और 7,391 तीसरी बार ऋण ले चुके हैं। इस प्रकार प्रदेश में अब तक कुल 11,94,176 लाभार्थियों को ऋण दिया जा चुका है, जिसकी कुल धनराशि 1452.74 करोड़ है।

चौराहों की सूरत बदल कर होगा सुन्दरीकरण : इंद्रजीत सिंह

- **नगर आयुक्त ने निरीक्षण कर लिया गया जायजा, दिए दिशा निर्देश**

लखनऊ। नगर आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नगर निगम तथा स्मार्ट सिटी के अधिकारियो के साथ अर्बन मोबिलिटी नोडस के तहत चौराहों के सौन्द्रियकरण कार्य के अंतर्गत मटियारी चौराहा, चिनहट चौराहा, कपूरथाला चौराहा एवं अल्कापुरी चौराहा का निरिक्षण किया गया।

नगर आयुक्त द्वारा चिनहट एवं मटियारी चौराहे पर अतिक्रमण हटाये जाने हेतु नगर निगम के उपस्थित अधिकारियो को निर्देशित किया गया।जिससे कि चौराहे पर स्मार्ट सिटी के तहत कराये जा रहे कार्यों मे कोई बाधा उत्पन्न ना होने पाए। साथ ही मटियारी चौराहे के साथ ही चिनहट चौराहा पर फुटपाथ को यथासंभव छोटा कर ब्लैक टॉप बढ़ाने एवं वर्षा ऋतु आने के दृष्टिगत चौराहे पर जल भराव की स्थिति पैदा होने से रोका जा सके। चौराहों पर ड्रेन बनवाए जाने, रोड का चौड़ीकारण, तथा झूल रहे तारो को अंदरग्राउंड करने, यूटिलिटी सिफ्टिंग करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।